दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

7

3 विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगारों से करता था ठगी

5 आदमखोर भेड़िये

8

UPHIN51019 | वर्षः 02, अंकः 11 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 09 सितम्बर, 2024

प्रधानमंत्री ने 'जल संचय जन भागीदारी पहल' की शुरुआत की

बोले– पूरे देश में बारिश से तबाही जारी

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने गुजरात में जल संचय, जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 'यह बेहद अहम पहल है, जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। हाल के दिनों में देश के हर कोने में भारी बारिश से तबाही जारी है। देश को कोई हिस्सा ही शायद होगा, जिसने इस प्राकृतिक आपदा की वजह से संकट न झेला हो। इस बार गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी मदद कर सकें, लेकिन गुजरात के लोगों और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं।'

टिकट बंटते ही भाजपा में बगावत...

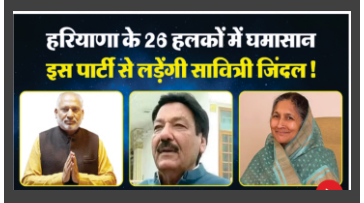

चंडीगढ़। भाजपा में टिकट बंटते ही बगावत हो रही है। हरियाणा के 26 हलकों में घमासान मचा है। मंत्री और विधायक समेत एक दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दिया है। पूर्व मंत्री ने तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही भाजपा में बगावत तेज हो गई है। करीब 22 विधानसभा सीटों पर भाजपा समर्थकों व पदाधिकारियों ने विरोध जताया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री समेत 14 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा व पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उधर, मंत्री विशंभर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री कविता जैन, सावित्री जिंदल, लतिका शर्मा के समर्थकों ने भी नाराजगी जताई है।

पार्टी के लिए बनेगी बड़ी चुनौती

पीछे हटने को तैयार नहीं पूर्व सांसद

लखनऊ/अयोध्या,संवाददाता

अयोध्या में भाजपा नेताओं की आपसी कलह पार्टी के लिए चुनौती बन रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों के बीच खींचतान से खेल बिगड़ सकता है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के पार्टी के कार्यक्रम के बहिष्कार से चर्चा तेज हो गई हैं। यूपी में विधानसभा उप चुनाव में सभी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य भेदने की तैयारी में जुटी भाजपा भले ही अंदरूनी कलह के खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन अयोध्या में पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपराधी होने का आरोप लगाकर पार्टी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि बड़े नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा के भीतर उठे अंदरूनी कलह की आग अभी भी सुलग रही है । ऐसे में माना जा रहा है कि अगर समय रहते पार्टी के भीतर के कलह को शांत नहीं किया गया तो उप चुनाव जीतने के लक्ष्य को भेदना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। वहीं, पार्टी स्तर पर अयोध्या की घटना को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व पूर्व सांसद की व्यक्तिगत नाराजगी मान रहा है।

सूत्रों का कहना है कि सांसद पार्टी से नहीं, बल्कि स्थानीय एक नेता से नाराज थे, इसलिए पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं हुए।

उधर दूसरी ओर नाम न छापने की शर्त भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है।

वैसे भी मुख्यमंत्री ने खुद इस सीट को जीताने की जिम्मेदारी ले रखी है। ऐसे में स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान पार्टी के प्रयासों में रोड़ा अटका सकता है। वहीं, भाजपा के रणनीतिकारों को भी यह चिंता सताने लगी है कि अगर अपने ही नेताओं मतभेद की स्थिति रही तो इससे पार्टी ही कमजोर होगी।

भाजपा नेताओं के बीच आपसी खींचतान ऐसे समय में सामने आई है, जब पूरा संगठन मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों में जुटा है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं।

पिछले दिनों इसी विधानसभा क्षेत्र में दो अलग–अलग कार्यक्रमों में सीएम शिरकत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस उपचुनाव में पार्टी की जीत हो, जिससे लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक सियासी संदेश प्रदेश के साथ पूरे देश में दिया जा सके। इसके इतर स्थानीय स्तर पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे ही हालात पैदा होने लगे हैं, तब भी पार्टी गुटों में विभाजित रही। इसका नतीजा रहा कि राममंदिर के निर्माण के साथ कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने के बाद भी पार्टी को प्रतिष्ठापरक फैजाबाद संसदीय सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या की इस सीट पर हार की गूंज देश ही नहीं, विदेश तक सुनाई देती रही।

यह था प्रकरण

बता दें कि पूर्व सांसद बुधवार को सर्किट हाउस में पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय की प्रेस कान्फ्रेंस को छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि मंच पर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा है और वे उसके साथ मंच साझा नहीं कर सकते। यह घटनाक्रम को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर भी चर्चाओं का बाजार गरम है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है।

पीछे हटने को तैयार नहीं पूर्व सांसद

पूर्व सांसद लल्लू सिंह मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पर वे इस तरह के विषयों को उठाते रहेंगे। पूर्व सांसद बृहस्पतिवार को कारसेवकपुरम में मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए ।

सुल्तानपुर एनकाउंटर

अखिलेश ने मुठभेड़ को फर्जी बताया

कहा– दो दिन पहले उठाए गए आदमी को मार डाला, कोर्ट दखल दे

लखनऊ। सुल्तानपुर सराफा कांड के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर तुरंत संज्ञान में ले। सुल्तानपुर में सराफा दुकान में डकैती को अंजाम देने वाले आरोपी का बृहस्पतिवार को हुए एनकाउंटर से प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है।

कहा, दो दिन पहले जिसको उठाने के बाद एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसका सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सुबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि यह प्रतीत होता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसीलिए नकली एनकाउंटर से पहले 'मुख्य आरोपी' से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। अन्य के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और एक की जाति देखकर उसकी जान ले ली गई। कहा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए। सरकार को पीड़ित कारोबारी को मुआवजा भी देना चाहिए।

भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल

उन्होंने कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। उन्होंने भाजपा राज को अपराधियों का अमृतकाल बताते हुए कहा कि जब तक जनता का रोष चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है। जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ को फंसाया जाता है।

कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है : योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग जाति, मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जाति के नाम पर दंगा करवाने वाले अखिलेश यादव अहंकार में बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं। माफिया ने राजू पाल की हत्या कर दी थी, तब कुर्सी की चिंता में कुछ नहीं बोले थे।

सजा देना अदालत का काम : शिवपाल

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सरकार के इशारे पर पार्टी बनने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है। किसी को सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत के पास है। सरकार को जवाब देना चाहिए। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

गुंडागर्दी सपा के डीएनए में : पाठक

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब सपा सत्ता में थी, तब अपराधियों ने सरकार की मदद से जनता को लूटा था। बहू–बेटियों की अस्मत लूटी जाती थी। गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना सपा के डीएनए में है। भाजपा सरकार हर हाल में अपराधियों का सफाया करेगी।

कांग्रेस के इस प्लान को देख बसपा सतर्क, ये रणनीति 'हाथी' को यूपी में और करेगी कमजोर, सपा पर भी बढ़ेगा दबाव

लखनऊ/अयोध्या,संवाददाता

कांग्रेस के इस प्लान को देखकर बहुजन समाज पार्टी सतर्क हो गई है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर दलित नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है। कांग्रेस की सक्रियता देख बसपा अपने नेताओं और वोट बैंक को सहेज रही है। लोकसभा चुनाव में अपने कैडर वोट बैंक का नुकसान सहने वाली बहुजन समाज पाटी के लिए प्रदेश में कांग्रेस बड़ा खतरा बनती जा रही है। कांग्रेस ने बसपा नेताओं को अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है, जिससे दलित वोट बैंक पर करीब चार दशक पुराना उसका वर्चस्व दोबारा स्थापित हो सके। कांग्रेस की इस रणनीति से बसपा यूपी में और कमजोर होगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का पलड़ा सपा पर भारी होता जाएगा। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अपनी पार्टी के उन नेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वह आरक्षण के उप–वर्गीकरण और क्रीमीलेयर के मुद्दे पर कांग्रेस की विचारधार का समर्थन नहीं करे। ऐसा करने वालों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक मायावती की इस चेतावनी की वजह बसपा नेताओं में कांग्रेस के प्रति बढ़ता आकर्षण माना जा रहा है। लोकसभा में करारी शिकस्त के बाद पार्टी नेताओं को बसपा के दोबारा सियासत में आने की संभावना खत्म होती दिख रही है। यही वजह है कि वह अपने राजनीतिक सफर को जारी रखने के लिए कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बीते दिनों बस्ती और चित्रकूट में बसपा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जो बसपा के लिए नुकसान का सबब बन गया।

नीट काउंसिलिंग 2024

एसएन की सीटें फुल, निजी कालेजों में 142 रह गईं खाली

आगरा। एसएन मेड़िकल कॉलेज आगरा में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग पूरी हो गई हैं। यहां सभी सीटें भर गई हैं। वहीं निजी कॉलेजों में 142 सीटें खाली रह गईं। आगरा के एसएन मेड़िकल कॉलेज में चल रही यूपी यूजी नीट–2024 की काउंसिलिंग में एसएन मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सभी सीटें भर गई हैं। इसमें 200 सीटें हैं, जिसमें यूपी कोटे की 170 सीटें हैं। निजी कॉलेजों में अभी 142 सीटें रिक्त हैं। इनके लिए 9 सितंबर को दोबारा काउंसिलिंग शुरू होगी। नोडल प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन समेत मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज, केएस मेडिकल कॉलेज और टूंडला के एफएच मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150–150 सीटें हैं। मथुरा के ही केडी डेंटल कॉलेज में बीडीएस की 100 सीटें हैं। इनमें 142 सीटें अभी खाली हैं। एसएन की यूपी कोटे की 170 सीटें भर चुकी हैं। बाकी 30 ऑल इंडिया कोटे की हैं। उन पर पहले ही प्रवेश हो गया है। इन सभी कॉलेजों की 900 सीटों में से 758 पर प्रवेश हो गया है। बची हुई सीटों के लिए 9 सितंबर से एसएन में फिर से काउंसिलिंग शुरू होगी।

सम्पादकीय

जम्मू–कश्मीर में राहुल का बड़ा वादा

जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल काफ्रेंस गठबन्धन ने प्रचार अभियान की शुरुआत बड़े वादे को दोहराते हुए कर दी है। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर के रामबन में एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 1947 में कांग्रेस की सरकार ने जम्मू–कश्मीर के राजा को हटाकर उसे राज्य का दर्जा दिया था लेकिन भाजपा सरकार ने पांच वर्ष पहले राज्य के दर्जे को समाप्त कर यहां एक राजा (लेफ्टीनेंट गवर्नर) को बैठा दिया है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि अब तक केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया जाता रहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी को अवसर मिला तो जम्मू–कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटायेगी। 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल काफ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पांच सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है।18 व 25 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर को यहां (तीन चरण) चुनाव होने जा रहे हैं।

जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल काफ्रेंस गठबन्धन ने प्रचार अभियान की शुरुआत बड़े वादे को दोहराते हुए कर दी है।

उल्लेखनीय है कि इस संवेदनशील राज्य में दस वर्षों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 5 अगस्त, 2019 को भाजपा सरकार ने जम्मू–कश्मीर के लिये लागू अनुच्छेद– 370 को हटा कर इसे और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसी साल विधानसभा का चुनाव होना था लेकिन वह इसी आधार पर टाल दिये गये थे। यहां चुनाव कराने की अनिच्छुक भाजपा की केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अंतर्गत चुनाव कराना लाजिमी हो गया है। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) गठबन्धन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन समझा जाता है कि ज़रूरी हुआ तो उसका समर्थन कांग्रेस–एनसी को मिल सकता है। अनुमान लगाये जा रहे हैं कि भाजपा से लोगों की इस कदर नाराज़गी है कि उसे कश्मीर में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सका है। कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद की भी राह कोई आसान नहीं मानी जा रही है। उसके अब तक 10 ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। माना जा रहा था कि उसका भाजपा से गठबन्धन हो सकता है लेकिन अब लगता है कि वह भाजपा की बी टीम के रूप में लड़ेगी। वैसे पहले ही उसके चार प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया है।

उधर दूसरी तरफ भाजपा अपनी रणनीति बनाने में मशगूल है लेकिन ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उसे जनता के बीच जाना मुश्किल हो जायेगा। पहली बात तो यही है कि अनुच्छेद– 370 हटाये जाने को लेकर वहां की जनता काफी नाराज़ है। उस प्रक्रिया के दौरान न तो वहां की जनता की राय ली गयी थी, न ही उसके बाद वे वादे पूरे हुए जिनका उल्लेख कर कहा जाता रहा कि जम्मू–कश्मीर के लोगों में खुशहाली आयेगी। जहां तक आतंकवादी घटनाओं से मुक्ति दिलाने की बात कही गयी थी, तो वैसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका। घाटी में अब भी पाक समर्थित आतंकी गुटों के हमले गाहे–बगाहे होते रहते हैं। इनमें मरने वालों की संख्या भी अच्छी–खासी है। कश्मीरी पंडितों की वापसी भी एक प्रमुख मुद्दा था जिसके बारे में भाजपा काफी दावे करती रही है। उस मोर्चे पर भी सरकार के हाथ खाली हैं। बहुत कम संख्या में कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई भी तो वे वहां स्थायी नहीं बसाये जा सके हैं। बाहरी मजदूरों की हत्याएं भी हुई हैं, कश्मीरी पंडित अब भी वहां कोई महफूज़ महसूस नहीं करते। जिस प्रकार से कश्मीरियों के बारे में भाजपा समर्थित लोगों ने अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और जैसे लम्बे समय तक घाटी के लोगों की इंटरनेट सुविधा छीनी गयी थी, उन सारी मुश्किलात का जवाब लेने का अवसर जम्मू–कश्मीर के लोगों को अब मिल गया है।

राहुल गांधी जम्मू–कश्मीर में बेहद लोकप्रिय हुए हैं। याद हो कि 7 सितम्बर, 2022 को कन्याकुमारी से निकली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी, 2023 को श्रीनगर में ही हुआ था जिसे पूरे देश की तरह ही जबर्दस्त प्रतिसाद मिला था। फ़ारुख़ अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि न केवल समापन रैली में शामिल हुए थे, बल्कि वे इंडिया गठबन्धन के भी हिस्सेदार हैं जो कई अवसरों पर हुई बैठकों एवं रैलियों में बराबर शिरकत करते रहे हैं। स्थानीय राजनीतिक ज़रूरतों के कारण एनसी एवं पीडीपी इस चुनाव में आमने–सामने बेशक हों, लेकिन उसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे उसने 'मिशन 66' के नाम से बनाये चुनावी अभियान पर काम शुरू कर दिया है। गठबन्धन की एकमात्र आशा छिपे समर्थक गुलाम नबी आजाद से हो सकती है लेकिन उनका कितना लाभ उसे मिलेगा, यह तो परिणाम ही बतलाएंगे। हाल ही में पीडीपी के चौधरी जुल्फीकार अली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल गनी ने भाजपा का दामन थाम लिया है।

कांग्रेस–एनसी का पलड़ा इसलिये भारी माना जा रहा है क्योंकि राहुल और उनकी पार्टी जम्मू–कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने का शुरू से ही विरोध करती आ रही है। रैली में राहुल ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम जो भी हों, उनकी पार्टी राज्य का दर्जा वापस दिलाने का संघर्ष करती रहेगी और केन्द्र सरकार को इसके लिये मजबूर करेगी। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिये लम्बित भर्तियां पूरा करने का भी आश्वासन दिया जो निश्चित ही मतदाताओं को आकर्षित करेगा।

मुस्तैद हो सुरक्षा

पश्चिम वंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से वलात्काररोधी विधेयक पारित कर दिया है जिसमें पीड़िता की मौत होने या उसके कोमा जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अपराजिता महिला एवं वाल विधेयक (पश्चिम वंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वलात्कार और यौन अपराधों से संवंधित नये प्रावधानों के जरिए महिलाओं और वच्चों की सुरक्षा मजवूत करना है। यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कानूनों और पॉस्को (यौन अपराधों से वच्चों को संरक्षण) अधिनियम, 2012 के पश्चिम वंगाल में क्रियान्वयन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद त्वरित जांच, जल्द से जल्द सुनवाई और दोपी को सख्त से सख्त सजा

दिलवाना है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के वाद से देश भर में रोप है। उसे न्याय दिलाने के लिए चिकित्सकों ने हड़ताल और प्रदर्शन भी किए। हालांकि यह विधेयक आसानी से पारित तो हो गया है मगर अभी इसे लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी है, जो मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं। सो, यह केंद्र सरकार तय करेगी कि यह विधेयक अधिनियम वनेगा या नहीं। दरअसल तो यौन अपराधों के खिलाफ अव सख्त कानून पहले से ही मौजूद हैं परंतु इस मामले में ममता सरकार पर शुरुआत से ही जांच में कोताही, आरोपियों को वचाने के प्रयास और साक्ष्य छिपाने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। सवसे वड़ी अदालत के सख्ती से यह कहने के वाद भी कि इस घटना का राजनीतिकरण न किया जाए राजनीतिक दलों द्वारा इसे चुनावी मुद्दा वनाने के प्रयास जारी हैं। यह कहने में गुरेज नहीं है कि महिलाओं और वच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में देश की तमाम राज्य सरकारें वुरी तरह असफल साविंत हुई हैं। इसलिए कि वे सिर्फ कड़े कानून वनाकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहती रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि केवल कानून द्वारा ही अपराधियों को काबू में नहीं किया जा सकता। सुरक्षा व्यवस्था में कोताही के प्रति जिम्मेदार लोगों पर भी लगाम कसी जानी जरूरी है। दोषियों को मृत्युदंड देने से वेहतर है, अपराधों की रोक-थाम के हर जरूरी प्रयास किया जाए। सामूहिक तौर पर सुरक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने के वेहतर उपाय किए जाएं।

एक और कानून, रेप के खिलाफ पहले से हैं सख्त ला

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल में असंतोष बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप 'अपराजिता' विधेयक पारित हुआ, जिसे जानकार गैरजरूरी मानते हैं। रेप के खिलाफ कड़े कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे असंतोष का कुल हासिल अगर 'अपराजिता' विधेयक का विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होना है तो इसे निराशाजनक ही कहना होगा। रेप पर नया कानून बनाने की इस पहल को जानकार लगभग एक स्वर में गैरजरूरी बता रहे हैं। कड़े कानून पहले से इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में रेप के खिलाफ कड़े कानून पहले से ही हैं। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद उभरे अभूतपूर्व जनअसंतोष का एक परिणाम कानूनों में बदलाव के रूप में भी सामने आया था, जिसके तहत रेप के लिए मौत की सजा तक के प्रावधान कर दिए गए थे। उसका काफी प्रचार भी हुआ था। बावजूद इस सबके, रेप के आंकड़ों में तो कमी नहीं ही आई, देश को सिहरा देने वाली कई बड़ी घटनाएं भी अंजाम लेती रहीं।

मौत की सजा की सीमा दरअसल, रेपिस्टों के लिए मौत की सजा की मांग जनभावनाओं के तात्कालिक उभार को शांत करने में भले सहायक हो, एक्सपर्ट्स पहले से कहते रहे हैं कि इससे अपराध को काबू करने में खास मदद नहीं मिलती। उलटे यह डर रहता है कि कहीं रेपिस्ट विक्टिम को मार ही न डाले क्योंकि उसे पता होता है कि रेप की सजा भी फांसी हो सकती है, लेकिन हत्या के बाद विक्टिम द्वारा पहचाने जाने की संभावना खत्म हो जाती है। अपराध साबित होना मुश्किल कानून में कड़ी सजा का प्रावधान करना मुश्किल नहीं।

राजनीति में झूठ बन रहा लोकतंत्र के 'अस्तित्व का खतरा'

20वीं सदी के मध्य में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक और लेबर पार्टी के नेता प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने अंततः मार्क्सवादी बनने से पहले धन शक्ति और झूठ पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास किया था। सत्ता पर कब्जा करने के लिए झूठ और धोखे को भुनाने की बात आने पर लोकतांत्रिक सरकार के पीछे असली राजनीतिक अभिनेता अज्ञात बने रह सकते हैं। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अक्सर सोचती हैं कि उनके मतदाता मूर्ख हैं। उनके पास ऐसी धारणा बनाने के अच्छे कारण हो सकते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चारित्रिक विशेषताओं के मामले में वहां रहने के लायक नहीं हैं। उनमें से कई पर तो जघन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मतदाताओं के पास उम्मीदवारों के चयन में बहुत कम विकल्प होते हैं।

वे मतदान केंद्रों पर ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से झूठे या जोड़–तोड़ करने वाले हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अक्सर उनके मतदाता झूठे वायदों पर मोहित होकर या बिक कर चुनते हैं कल्पना करें कि अगर राजनीति में झूठ बोलना प्रतिबंधित कर दिया जाये तो सरकार में बैठे उन आदतन झूठ बोलने वालों का क्या होगा जो अर्थव्यवस्था और प्रशासन की झूठी छवि बनाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार, ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से वेल्श की नवनिर्वाचित लेबर सरकार ने राजनीति में झूठ बोलने को अवैध बनाने का संकल्प लिया है। वेल्श सरकार ने कहा कि 2026 में अगले सेनेड (वेल्श संसद) चुनावों से पहले 'विश्व स्तर पर अग्रणी' कानून बनाया जायेगा। सेनेड के सदस्यों ने इसे लोकतंत्र में. राजनीति में झूठ बोलने से उत्पन्न 'अस्तित्वगत खतरे' से निपटने के अपने प्रयास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

वेल्श सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जानबूझ कर धोखा देने के दोषी पाये गये सदस्यों और उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करेगा। राजनेताओं द्वारा झूठ बोलने को गैरकानूनी घोषित करने के आह्वान का नेतृत्व कर रहे एक प्रमुख वेल्श राजनेता एडम रॉबर्ट प्राइस ने कहा थाः 'जो घोषणा की गई है वह वास्तव में ऐतिहासिक है, विश्व स्तर पर अग्रणी है। हमारी सरकार की ओर से हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारा लोकतंत्र राजनेताओं द्वारा धोखे पर सामान्य प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला लोकतंत्र होगा। हम एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत में हैं। हम राजनीतिक झूठ को गैरकानूनी घोषित करने जा रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि 'सत्य लोकतंत्र के दिल में है, लेकिन राजनेताओं में विश्वास खत्म हो गया है। यह एक अस्तित्वगत खतरा है।' उन्होंने कहा, 'अगर मतदाता निर्वाचित लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो लोकतंत्र टूटने लगता है।' हालांकि, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सहित दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रस्तावित वेल्श कानून के प्रभाव की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, जो ग्रेट ब्रिटेन के दो

लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अक्सर सोचती हैं कि उनके मतदाता मूर्ख हैं। उनके पास ऐसी धारणा बनाने के अच्छे कारण हो सकते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चारित्रिक विशेषताओं के मामले में वहां रहने के लायक नहीं हैं

अन्य घटक हैं, लेकिन यह कुछ लोकतांत्रिक देशों में आंदोलन को जन्म दे सकता है। वेल्श एक बहुत छोटा देश है, जो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। 2021 तक, वेल्श की आबादी 3,107,494 थी और इसका कुल क्षेत्रफल 21,218 वर्ग किलोमीटर था। इसलिए, वेल्श में जो कानूनी रूप से संभव हो सकता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों में उम्मीद करना असंभव हो सकता है, जहां झूठ बोलना पार्टी की राजनीति का एक अभिन्न अंग है, जो राजनेताओं की आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करता है और बेहद कम अभियोजन और सजा दर दर्ज करता है। झूठ बोलने वाले राजनेता की पहचान की जा सकती है और उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसे राजनेताओं द्वारा चलाई जाने वाली झूठ बोलने वाली सरकार के बारे में क्या, जो अक्सर झूठ बोलते हैं और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं?

भारत में स्थिति की कल्पना करें, जहां राजनीतिक शासक अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता या मतदाताओं को गुमराह करने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अक्सर महत्वपूर्ण संख्याओं में हेराफेरी करवाते हैं। यह बढ़ती महंगाई या घटते रोजगार या संदिग्ध वित्तीय लेन–देन के समय में झूठी खुशी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

ऐसे सरकारी कार्यों के बारे में क्या जो राष्ट्र की कीमत पर केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों या समूहों को लाभ पहुंचाते हैं? ऐसे कार्यों के पीछे व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाये? सरकार अपने सार्वजनिक संचार इरादे के अनुरूप संबंधित टोकरियों को बड़ा या छोटा करके आधिकारिक सूचकांकों में हेराफेरी कर सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसे समय में जब खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, संचार और यात्रा लागत, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय और उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, भारत में थोक और खुदरा मूल्य सूचकांक दोनों में बड़ी गिरावट बताई जा रही है। कोई उन्हें उन टोकरियों के आकार पर दोष दे सकता है जिनमें उन दैनिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इस तरह के सरकारी धोखे से कैसे निपटें? लोकतांत्रिक समाज में सरकारी धोखे पर कई बार बहस हुई है, जिससे लोकतांत्रिक दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र में झूठ का प्रसार हुआ है। लोग एक चुनी हुई सरकार पर भरोसा करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार के भ्रामक कार्यों और बयानों पर भी भरोसा कर लेते हैं। वास्तव में, सरकार के झूठ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए किसी एक राजनेता के सार्वजनिक झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सरकार के झूठ का असर विधायिका और न्यायपालिका पर भी पड़ता है।

तीन वर्ष से थे प्रेम–प्रसंग में, प्रेमी ने शादी से किया इंकार– प्रेमिका ने की थाने में ही खुदकुशी की कोशिस

गोरखपुर,संवाददाता। गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का पड़ोस के गांव के युवक से तीन वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसमें युवती उससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन युवक इससे मुकर रहा था। इसे लेकर युवती ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने जब जांच कर मुकदमा दर्ज करने की बात कही तो युवती ने मना कर दिया। थाने में ही महिला ने आत्मदाह की कोशिस कर ली। गोरखपुर के गोला इलाके के एक गांव की युवती ने बुधवार को गोला थाना परिसर में ज्वलनशील पदार्थ गिराकर आग लगाने की कोशिश की। इसे देख एक फरियादी ने युवती के हाथ से माचिस छीनकर उसकी जान बचाई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी उसे थाने के अंदर लेकर चली गईं। घटना की जानकारी होने पर एसपी साउथ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।

गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का पड़ोस के गांव के युवक से तीन वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसमें युवती उससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन युवक इससे मुकर रहा था। इसे लेकर युवती ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने जब जांच कर मुकदमा दर्ज करने की बात कही तो युवती ने मना कर दिया। इसी बीच युवक व युवती में समझौता हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद युवक ने दोबारा शादी से मना कर दिया। युवती फिर थाने पहुंची और शिकायत की। उसका आरोप है कि पुलिस उसे दो महीने से दौड़ा रही थी। जिससे वह परेशान हो चुकी थी।

दबाव बनाकर शादी कराने को थाने का लगा रही थी चक्कर

युवती के साथ युवक शादी से मना कर रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों में वार्ता भी हुई थी। युवक से जुड़े लोग रुपये देकर छुटकारा पाना चाह रहे थे। इसके बाद युवती ने दबाव बनाने के लिए थाने का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वह दो माह से थाने आ रही थी। पुलिस से दबाव बनवाकर युवक से शादी करना चाहती थी। हर बार थाने से उसकी बात को अनसुना कर भगा दिया जा रहा था। जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्मघाती कदम उठाने का निर्णय ले लिया।

चकसरया के युवक ने बचाया

मौके पर पहुंचे चश्मदीद चकसरया निवासी एक युवक ने बताया कि युवती एक लीटर के प्लास्टिक के बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेकर थाने में अंदर की तरफ गई और अपने ऊपर उसे उड़ेल लिया। माचिस की तीली निकालकर खुद को जलाने ही जा रही थी कि उसने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवती ने युवक के विरुद्ध आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज कराना चाह रही थी। उसका कहना था कि जेल जाने के बाद युवक शादी नहीं करेगा। दोनों ने थाने में समझौता भी किया था, परंतु मामला बिगड़ने पर युवती दोबारा थाने आकर शिकायत की। केस न दर्ज करते हुए युवक पर दबाव बनवाकर शादी कराने की बात कह रही थी। उससे तहरीर लेकर मुख्य आरोपी अंकित व उसके परिजनों पर केस दर्ज कर दिया गया है।

विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगारों से करता था ठगी

10 हजार का था इनामी– गिरफ्तार

गोरखपुर। सीओ पीपीगंज गौरव त्रिपाठी ने बताया कि अजय कुमार ने तीन महिला संग 3 मई को पीपीगंज थाना में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि नौकरी के नाम पर उनके साथ ठगी हो गई है। उनके अलावा तकरीबन 120 लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर निकेतन त्रिपाठी फरार चल रहा था। पीपीगंज इलाके के एक ग्राम सभा में ट्रेनिंग एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर खोल विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले दस के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, इंद्रानगर वार्ड नंबर 13 देवरिया के निवासी अजय कुमार ने तीन महिला 3 मई को पीपीगंज थाना में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि पीपीगंज के जंगल कौडिया में निकेतन त्रिपाठी नाम का युवक शीतल ट्रेनिंग एण्ड ट्रेड सेंटर खोलकर लगभग 130 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं।

वह फर्जी वीजा व टिकट देकर धोखाधड़ी कर रुपए सारे रुपए लेकर फरार हो गया है। जिसके बाद पीपीगंज पुलिस ने धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की खोजबीन में जुट गई थी। जिसके बाद से पीपीगंज पुलिस खोजबीन में जुटी थी। जिसे बुधवार के दिन छपरा थाना खोराबार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बदल रहा है गोरखपुर

216.19 करोड़ की लागत से

4.2 किलोमीटर की सड़क फोरलेन बनाई जाएगी।

राजघाट से महेसरा पुल तक बनेगा फोरलेन..

नेपाल की राह होगी आसान

गोरखपुर,संवाददाता। हार्बर्ट बंधा से डोमिनगढ़ तक 216.19 करोड़ की लागत से 4.2 किलोमीटर की सड़क फोरलेन बनाई जाएगी। इसके बाद डोमिनगढ़ रेलवे लाइन पर हार्बर्ट बंधा और माधोपुर बंधा को जोड़ने के लिए 650 मीटर लंबे ओवरब्रिज का निर्माण सेतु निगम करीब 110 करोड़ की लागत से कराएगा। इसके आगे माधोपुर बंधा होते हुए बसियाडीह के रास्ते महेसरा पुल तक 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क भी फोरलेन बनाई जाएगी।

राजघाट के हार्बर्ट बंधा से माधोपुर–बसियाडीह के रास्ते महेसरा पुल तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। हार्बर्ट बंधा से महेसरा पुल तक 14. 4 किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण से नेपाल व सोनौली की राह आसान हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण को लेकर सर्वे का कार्य पूरा करने के बाद आगे की प्रक्रिया में जुट गया है।

हार्बर्ट बंधा से डोमिनगढ़ तक 216.19 करोड़ की लागत से 4.2 किलोमीटर की सड़क फोरलेन बनाई जाएगी। इसके बाद डोमिनगढ़ रेलवे लाइन पर हार्बर्ट बंधा और माधोपुर बंधा को जोड़ने के लिए 650 मीटर लंबे ओवरब्रिज का निर्माण सेतु निगम करीब 110 करोड़ की लागत से कराएगा। इसके आगे माधोपुर बंधा होते हुए बसियाडीह के रास्ते महेसरा पुल तक 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क भी फोरलेन बनाई जाएगी।

पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड–2 को इस फोरलेन के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे पूरा कर लिया है। अब निर्माण के लिए सीमांकन किया जा रहा है। 9–9 मीटर चौड़ीकरण के बाद सड़क के दोनों तरफ डेढ़–डेढ़ मीटर का नाला व एक मीटर का डक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही डेढ़ मीटर का डिवाइडर और दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण भी कराया जाना है।

पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन अरविंद सिंह ने बताया कि राजघाट पर हार्बर्ट बंधा से डोमिनगढ़ तक 4.2 किमी व माधोपुर बंधा से बसियाडीह होते हुए महेसरा पुल तक 10.2 किमी सड़क को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों बंधों को जोड़ने के लिए डोमिनगढ़ रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज का भी निर्माण होना है।

सांसद रवि किशन ने कहा– अखिलेश यादव ने प्रदेश के 75 जिलों में गोरखपुर ही क्यों चुना

गोरखपुर,संवाददाता। गोरखपुर में सदस्यता अभियान के तहत सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने और सांसद रवि किशन ने प्रेस वार्ता की। रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति और सवाल भी उठाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि उन्होंने गोरखपुर की जनता की आस्था पर प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आखिर क्यों उन्होंने गोरखपुर को चुना?

इसका सवाल अखिलेश यादव खुद बताएं क्योंकि उन्हीं से इस सवाल का जवाब चाहिए। कहने का मकसद क्या रहा, यह वही बताएं। कहा, गोरखनाथ मंदिर यहां के लोगों की आस्था का केंद्र है और अखिलेश यादव का ये बयान यहां के लोगों की आस्था पर प्रहार है। उनके कहने का सीधा मतलब यही है। ऐसे में खुद बताएं कि आखिर गोरखपुर का नाम लेकर उन्होंने लेकर क्यों कहा?

लिव इन में रह रहे युवक की मौत, महिला मित्र समेत 5 पर हत्या का आरोप–

गोरखपुर। गोरखपुर क्षेत्र के मोगलहा में लिव इन में रह रहे एक युवक की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। युवक के बड़े भाई ने महिला मित्र और चार साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गोरखपुर क्षेत्र के मोगलहा में लिव इन में रह रहे एक युवक की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। युवक के बड़े भाई ने महिला मित्र और चार साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गगहा के लोहरापार निवासी आर्य प्रकाश बीआरडी मेडिकल कालेज के उत्तरी गेट के पास एक हास्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। एक माह पहले प्रशासन ने हास्पिटल को सील कर दिया तो वह यहां काम कर रही महिला मित्र के साथ मोगलहा में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। खर्च चलाने के लिए वह इधर–उधर काम कर रहा था। दोपहर में अचानक आर्य प्रकाश के मौत की सूचना उसके घरवालों को दी गई। बड़े भाई जयप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि मंगलवार की दोपहर 11:45 बजे आर्य प्रकाश ने भाई शशिप्रकाश से फोन पर बात की थी। जिसमें उसने सबकुछ ठीक बताया था, लेकिन एक घंटे बाद जब शशि ने फोन किया तो मोबाइल नहीं उठा।

कुछ देर बाद एक युवक का फोन जयप्रकाश के मोबाइल पर आया और उसने बताया कि आर्य की मौत हो चुकी है। फिर महिला मित्र ने भी फोन किया और मौत की सूचना दी। जयप्रकाश ने बताया कि उसके भाई का मोबाइल फोन महिला की फिंगर से खुलता है। उसने पहले बताया था कि भाई की तबीयत बहुत खराब है। मेडिकल कालेज ले जाया जा रहा है। इसके बाद महिला मित्र चार युवकों के साथ आर्य को मेडिकल कालेज ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से ही सभी फरार हैं। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं मिले हैं। विसरा सुरक्षित किया गया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

कोचिंग पढ़कर घर जा रही छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

गोरखपुर। छात्रा की मां ने पुलिस को बताया है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी दसवीं की छात्रा है। बेटी स्कूल से छूटने के बाद कोचिंग पढ़कर शाम छह बजे तक घर आती है। 29 अगस्त को छात्रा कोचिंग पढ़कर साइकिल से घर आ रही थी। शाम 5: 45 बजे सखरुआ और मुर्तनवा के बीच सुनसान स्थान देखकर निखिल ने अपने दोस्त किशन के साथ उसे पकड़ लिया और दोनों छेड़खानी करने लगे।

गोरखपुर जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़कर घर जा रही छात्रा से दो मनबढ़ों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों एक सप्ताह से छात्रा का पीछा कर रहे थे। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां, आरोपियों के घर उलाहना लेकर गई तो उसे मारपीट कर भगा दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर छात्रा की मां ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की।

उनके निर्देश पर तीन सितंबर को गुलरिहा पुलिस ने मुख्य आरोपी निखिल विश्वकर्मा, साथी किशन नारायण सिंह पर केस दर्ज किया। इसके अलावा मारने–पीटने के आरोप में किशन के भाई राज नारायण सिंह व उसके पिता जगदीश नारायण सिंह के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, छात्रा की मां ने पुलिस को बताया है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी दसवीं की छात्रा है। पति बाहर रहकर काम करते हैं। बेटी स्कूल से छूटने के बाद कोचिंग पढ़कर शाम छह बजे तक घर आती है। 29 अगस्त को छात्रा कोचिंग पढ़कर साइकिल से घर आ रही थी।

शाम 5: 45 बजे सखरुआ और मुर्तनवा के बीच सुनसान स्थान देखकर निखिल ने अपने दोस्त किशन के साथ उसे पकड़ लिया और दोनों छेड़खानी करने लगे। इसके बाद दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर राहगीरों के पहुंचने पर वे उसे छोड़कर फरार हो गए। छात्रा ने घर पहुंचकर मां को आपबीती बताई। अगले दिन 30 अगस्त की सुबह मां आरोपी के घर उलाहना लेकर गई तो उसके भाई और पिता ने गाली देते हुए लाठी लेकर दौड़ा लिया। किसी तरह से जान बचाकर वह घर पहुंची।

फिर थाने पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और एससी–एसटी का केस दर्ज किया गया है। सीडीआर की जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी और छात्रा साथ में पढ़ते थे। दोनों में बातचीत पहले से हो रही थी। मामले की जांच की जा रही है।

गांवों में रातभर जागते रहो का पहरा

भेड़ियों ने वन विभाग को छकाया...

हांफ रहे जिम्मेदार, बकरी को बनाया निवाला

बहराइच,संवाददाता। भेड़ियों की दहशत से महसी तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के लोग सहमे हुए हैं। कार्रवाई के लिए सेक्टरवार टीमें तैनात की गई हैं। लेकिन भेड़िये लगातार उन्हें चकमा दे रहे हैं। बुधवार रात भेड़िये ने हरदी थाना क्षेत्र के पचदेवरी में बकरी को निवाला बना लिया। दो बकरियों को घायल भी किया। पचदेवरी के मजरा राम दहिनपुरवा निवासी विधवा रंजना बकरी पालन कर परिवार चलाती हैं। बुधवार की रात वह अपनी चारों बकरियों को आंगन में बांधकर सो गईं। इस दौरान पहुंचे भेड़िये ने एक बकरी को मारकर दो को घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस व वन टीम ने घर के आसपास भेड़िये की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आ सका।

दहशत में ग्रामीण

भेड़िये के हमले के बाद से पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया कई बार देखा गया है। गनीमत रही कि भेड़िया ने रंजना या अन्य परिजनों पर हमला नहीं किया।

मंगलपुरवा में कैमरे में कैद हुआ भेड़िया

हरदी थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा गांव में मंगलवार को एक भेड़िया गन्ने के खेत के पास देखा गया। ग्रामीणों ने उसकी फोटो कैमरे में कैद करते हुए वन टीम को सूचना दी, लेकिन भेड़िया वनकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला।

सुबह सात बजे सर्च आपरेशन

पचदेवरी क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह भी भेड़िया दिखा, जिसके बाद सुबह सात बजे वन व शूटिंग टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर शाम तक सफलता नहीं मिली।

सेक्टरवार शुरू हुआ अभियान, तीन डीएफओ बने नोडल

ऑपरेशन भेड़िया को सकुशल संपन्न करने के लिए महसी क्षेत्र को तीन सेक्टरों में बांट कर टीमें तैनात कर दी गईं हैं। प्रभावी कार्रवाई के लिए हर सेक्टर में डीएफओ स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने टीम में लगे अधिकारियों के नंबर भी सार्वजनिक करते हुए डीएफओ कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया है।

शिक्षक सम्मान समारोह: गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा,'राष्ट्र व समाज निर्माता के रूप में खुद को तैयार करें शिक्षक'

गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक को नवाचार पर काम करना चाहिए। सीएम योगी ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 41 शिक्षकों को सम्मानित किया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक को नवाचार पर काम करना चाहिए। पढ़ाई के आसान तरिके के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वे स्कूल का वातावरण अध्यात्मिक बनाने पर काम करें। आत्मनिर्भरता दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 41 शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया है, इसमे पुरस्कृत होने शिक्षकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ताकि इनके अनुभवों का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि व्यक्ति में श्रद्धा का भाव जरूरी है, जिसमें यह भाव न हो ज्ञानी नहीं हो सकता है।

69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों ने यूपी के मंत्री डा. संजय निषाद का आवास घेरा, बोले– नियुक्ति दें

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को यूपी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए नियुक्ति की मांग की। 69000 शिक्षक भर्ती के अथ्यर्थी प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन कर अपना पक्ष रख रहे हैं।

शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने सरकार पर भर्ती में आरक्षण का घोटाला करने का आरोप लगाया है और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। इसके पहले अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल के आवास का भी घेराव किया।

सात सितंबर को मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे अभ्यर्थी

बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने व नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सात सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए उन्होंने पांच अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे।

धरना–प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा अभ्यर्थी चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है तो इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भर्ती की मूल चयन सूची रद्द कर सरकार को तीन महीने में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सात सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा।

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, आंसुओं के सैलाब में डूबा गांव

बाराबंकी । हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह इनके शव गांव पहुंचे। मरने वाले पांच लोगों में चार एक ही परिवार के हैं। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों समेत पांच की मौत हो गई थीं।

डीएम के निर्देश में डॉक्टरों की टीम ने रात में ही पोस्टमार्टम शुरू किया। सुबह करीब 10 बजे पांचों शव कुर्सी थाना क्षेत्र के उमरा गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। परिजनों की चीत्कार देखकर पूरा गांव रो पड़ा। बृहस्पतिवार की सुबह अधिकतर घरों में चूल्हा तक नहीं जला।

दोपहर में सभी शवों का अंतिम संस्कार पुलिस के मौजूदगी में शुरू हुआ। मरने वाले सभी मुस्लिम परिवार के है।

मालूम हो कि लखनऊ–महमूदाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात बड्डूपुर क्षेत्र के इनैतापुर गांव के पास दो कार व एक ऑटो में भीषण टक्कर हो गई थी इसमें एक कार सड़क के बगल तालाब में चली गई। इस हादसे में ऑटो सवार कुर्सी थाना क्षेत्र के उमरा गांव निवासी इरफान पुत्र एहतेशाम, वहिदून निशा पत्नी स्वर्गीय अनवार अली, अजीज अहमद उर्फ बुद्धू पुत्र मुहर्रम अली, ताहिरा बानो पुत्री जाकिर अली व साबरीन पत्नी तारिक काजमी की मौत हो गई थी जबकि शायरा बानो पत्नी अजीज अहमद, एक बच्ची अक्सा पुत्री सारिक, कार चालक नंदना खुर्द गांव का विवेक घायल हैं।

एसपी दिनेश कुमार ने बताया की रात करीब 2:30 बजे बैटरी व महिला को कैदियों में रेफर कर दिया गया जहां दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे में जान गवाने वाला इरफान ही एक दूसरे परिवार का है बाकी चार एक ही परिवार के हैं।

इस घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद पी एल पुनिया उमरा गांव पहुंच गए हैं। दरियाबाद के विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश सिंह शर्मा ने घटना पर गहरा दुख जताया है।

आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाया ये प्लान...

वनकर्मियों के हाथों में लाठी–डंडा और जाल

बहराइच में प्रभावी कार्रवाई के लिए भेड़िया प्रभावित क्षेत्र को वन विभाग ने तीन सेक्टर में बांट दिया है। सभी में 20–20 टीमों की तैनाती की गई है। महसी तहसील क्षेत्र में औराही को सेक्टर एक, पूरे दिलदार सिंह को सेक्टर दो व बंशपुरवा को सेक्टर तीन बनाया गया है। इन क्षेत्रों में जागरूकता के लिए भी तीन टीमें तैनात की गई हैं।

अभियान की समीक्षा के लिए बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. संजय निषाद, वन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना व अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार बहराइच पहुंचे। सभी ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर हमलों की रोकथाम व भेड़ियों को पकड़ने की रणनीति बनाई।

बैठक में मौजूद वन, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य व ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मंत्रियों ने कहा कि सभी आपस में बेहतर तालमेल रखें और युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें। सभी विभाग अपने–अपने एक नोडल अधिकारी नामित करें। सर्च ऑपरेशन में लगाई गई टीमों का विवरण जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराएं। मंत्रियों ने विद्युत विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, वहीं मेडिकल कॉलेज व अन्य अस्पतालों की इमरजेंसी व एंबुलेंस को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। मंत्रियों ने लोगों को बाहर सोने से रोकने के लिए जागरूक करने की भी बात कही।

आखिरी आदमखोर के खात्मे पर ही राहत

सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में 1997 के दौरान भेड़ियों का जबरदस्त आतंक रहा था। तब इन इलाकों में भेड़ियों ने 42 बच्चे मार दिए थे। अखिल भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी वीके सिंह के मुताबिक 1997 में जब एक भेड़िया पकड़ते या मारते थे, तो खुशी होती थी कि चलो अब निजात मिती। अगले ही दिन फिर कहीं से हमले की सूचना आ जाती। इससे सबक मिला कि जब तक इंसान के बच्चों को मारने वाले असली अपराधी भेड़िये नहीं मारे जाते हैं, तब तक हमले नहीं थमेंगे। बहराइच में ही चार भेड़ियों को पकड़ने के बाद भी इंसानों पर हमले नहीं रुके हैं। साफ है कि असली आदमखोर अभी तक पकड़ा या मारा नहीं गया है।

लखनऊ,संवाददाता। यूपी में विलुप्तप्राय भेड़िये इंसानी जान के लिए संकट बने हुए हैं। इनके हमले में मार्च 2024 से अब तक बहराइच में नौ बच्चों और महिला की मौत हुई है। साथ ही सीतापुर, पीलीभीत और हस्तिनापुर में भी भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बड़ी मशक्कत के बाद बहराइच से चार भेड़िये पकड़े गए हैं। इसके बाद भी इंसान और भेड़ियों के बीच जारी संघर्ष से अंदेशा लगाना मुश्किल नहीं है कि असली हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इंसानों को शिकार बनाने वाले असली भेड़िये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लिहाजा, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को ज्यादा संजीदगी के साथ अभियान चलाने की जरूरत है।

साथी को बचाने के लिए दे देते हैं जान

भेड़िये अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कई बार लोग फर्क नहीं जानने के कारण कुत्तों को भेड़िया समझ लेते हैं। वैसे सामान्य तौर पर भेड़िये आदमखोर नहीं होते हैं। वे इंसानी आबादी के आसपास ही जंगल और खखेतों में छिपकर रहते हैं। पाठक बताते हैं कि भेड़ियों पर बाघ से ज्यादा विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 होगी। वहीं, पूरे देश में 2– 3 हजार ही भेड़िये होंगे। इनकी गणना न होने से वास्तविक संख्या बताना काफी मुश्किल है। हालांकि, लोगों के मुताबिक भेड़ियों की संख्या कहीं ज्यादा है।

बेहद शर्मिला जानवर है भेड़िया

बार–बार सवाल उठ रहा है कि भेड़िये आदमखोर क्यों हो रहे हैं? क्या इनकी संख्या बढ़ रही है? दुधवा टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर व वन्यजीव विशेषज्ञ संजय पाठक के मुताबिक, भेड़िया बेहद शर्मीला जानवर है। ये इंसान को देखते इतना तेजी से भाग जाता है कि इनकी फोटोग्राफी करना भी आसान नहीं होता है। यह इंसानों की तरह झुंड में रहता है। अगर शिकार के बाद कोई एक सदस्य इधर–उधर गुम हो जाए तो बाकी सदस्य उसको खोज निकालने तक शिकार को छूते तक नहीं हैं। संजय पाठक बताते हैं कि ये इंसानों पर तभी हमला करते हैं, जब बाढ़, मांद में पानी घुस आने या अन्य किसी कारण से इन्हें अपना प्राकृतिक वास छोड़ना पड़ता है और इस प्रक्रिया में कहीं उनकी जद में इंसान का कोई बच्चा आ जाता है। उसके बाद बच्चों पर हमला करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगर इंसान भेड़ियों के झुंड के किसी सदस्य को मार देता है तो भी उनके अंदर बदले की भावना घर कर जाती है और वे हमला करने लगते हैं।

वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि आम तौर पर देखा गया है कि झुंड का कोई एक सदस्य इंसान के बच्चे पर हमला करता है। भेड़िया जो मांस खुद खाता है, बाद में उसे उल्टी करके अपने बच्चों को खाने के लिए निकाल देता है। इस तरह से उस झुंड के सदस्यों को इंसान का मांस खाने का चस्का लग जाता है। यही आदमखोर प्रवृत्ति इंसानों के लिए खतरा बन जाती है।

वन्जीव विशेषज्ञ बताते हैं कि भेड़िये इतने सामाजिक प्राणी होते हैं कि अपने सहगामी की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कई बार लोग भेड़ियों और कुत्तों में फर्क नहीं कर पाते और कुत्तों को भी भेड़िया समझ लेते हैं। समझने की बात यह है कि आम तौर पर भेड़िये आदमखोर नहीं होते। इंसानों की आबादी के आसपास ही जंगल या खेतों में छिपकर रहते हैं।

संजय पाठक बताते हैं कि ये इंसानों पर तभी हमला करते हैं, जब बाढ़, मांद में पानी घुस आने या अन्य किसी कारण से इन्हें अपना प्राकृतिक वास छोड़ना पड़ता है और इस प्रक्रिया में कहीं उनकी जद में इंसान का कोई बच्चा आ जाता है। उसके बाद बच्चों पर हमला करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।

आदमखोर भेड़िये

हमलों से साफ है

साथी को बचाने के लिए दे देते हैं जान

कब करते हैं हमला और कैसे लगता है इंसानी मांस का चस्का

भेड़िये इंसानों पर तभी हमला करते हैं, जब बाढ़, मांद में पानी भरने या दूसरे कारण से इन्हें अपना प्राकृतिक वास छोड़ना पड़ता है। इस दौरान अगर उनकी जद में इंसान का बच्चा आ जाए तो इनकी हमला करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर इंस्खन उनके झुंड के किसी सदस्य को मार दे तो वे बदले के लिए हमला करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक भेड़िया इंसान पर हमला कर खुद उसका मांस खाता है। फिर उल्टी कर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है। इससे उन्हें भी इंसानी मांस खाने का चरका लग जाता है।

दिल्ली,एजेंसी। 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के अध्यक्ष के अनुसार, आज भारत में तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी सेलरी से हर महीने 10 प्रतिशत अंशदान कटौती की जाती है। इसके एवरेज में सरकारी 14 प्रतिशत की रकम कंट्रीब्यूट करती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। अगले वर्ष पहली अप्रैल से यह योजना लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार को दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं, जो अभी यूपीएस पर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक जो विपक्षी दल ओपीएस के समर्थन में खड़े थे, आज उनमें से अधिकांश पार्टियां, खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। आखिर, 91 लाख एनपीएस कर्मी और 12000 करोड़ रुपए महीना, इसे लेकर क्या पर्दे के पीछे कोई सच्चाई छिपी है। प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी 'ओपीएस' पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, संभव है कि एनपीएस को खत्म कर हुबहू ओपीएस बहाल करना एक शगूफा मात्र हो। उन्होंने कई ऐसे कारण गिनाए हैं, जिनके चलते 'राष्ट्रीय दल' ओल्ड पेंशन स्कीम को कोर मुद्दे के तौर पर अपनाना नहीं चाहते।

डॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, देश में लंबे समय से ओपीएस बहाली के मुद्दे पर चर्चा जारी है। कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन किए हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का रुझान पोस्टल बैलट पर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ दिखाई दिया। इसके बाद 24 अगस्त को, भारत सरकार द्वारा गठित की गई एनपीएस रिव्यू कमिटी के मुखिया टीवी सोमनाथन ने नई पेंशन स्कीम के समानांतर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मसौदा पेश कर दिया। देश की ज्यादातर हिस्सों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। अब मुद्दा यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को उसके मूल रूप में बहाल किया जा सकता है। हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मतलब है कि पहले वर्तमान एनपीएस सिस्टम को खत्म किया जाए। उससे पहले भी हम यह देखते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में अपना समर्थन दिया या उसकी बहाली के पक्ष में खड़े हुए उनकी सच्चाई क्या है। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने बताया, लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए थे। आंदोलन के मंच पर लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी वहां पधारे थे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबसे बड़े विपक्षी दल ने गत वर्ष कर्मचारियों की अक्टूबर में हुई रैली को तो समर्थन दिया था, लेकिन उसके ठीक दो महीने बाद जब लोकसभा चुनाव की सुविधा शुरू हुई तो उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में इसे शामिल नहीं किया। उनके मेनिफेस्टो में 25 न्याय की गारंटी शामिल थीं। पुरानी पेंशन का मुद्दा, जिस पर विपक्षी दल वर्तमान सरकार को हर जगह घूरते हुए नजर आ रहे थे, इस दल के मेनिफेस्टो से ओपीएस का मुद्दा ही गायब था। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के नेताओं ने विपक्षी दलों के पदाधिकारियों से अलग–अलग जगह पर मुलाकात की। उनसे आग्रह किया गया कि वे ओपीएस को अपने चुनावी मेनिफेस्टो में शामिल करें। कर्मचारी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए कि विपक्षी दल के सप्लीमेंट्री मेनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा शामिल किया जाएगा। हालांकि बाद में कुछ नहीं हो सका।

राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख विपक्षी दल ने इस मुद्दे को न तो अपने मेनिफेस्टो में शामिल किया और न ही इसके लिए सप्लीमेंट्री मेनिफेस्टो जारी किया। जब विपक्षी राष्ट्रीय दल ने अपने मेनिफेस्टो पर प्रेस वार्ता की तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल न किए जाने पर सवाल किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस मुद्दे पर गोल–गोल जवाब देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। कहा, अभी कमेटी की रिपोर्ट आने दें। जब उनकी सरकार आएगी, तब वे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उनकी नजर इस मुद्दे पर है। इसके बाद चुनावी रैलियों में कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा मेनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन अंडर कंसीडरेशन है। हालांकि राजनीति में अंडर कंसीडरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। डॉ. मंजीत पटेल ने बताया, अब बात करते हैं कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम, हुबहु बहाल की जा सकती है। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि एनपीएस को अगर खत्म किया जाए तो उसका वर्तमान आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक बड़ा एवं अहम सवाल है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के अध्यक्ष के अनुसार, आज भारत में तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी सेलरी से हर महीने 10 प्रतिशत अंशदान कटौती की जाती है। इसके एवरेज में सरकारी 14 प्रतिशत की रकम कंट्रीब्यूट करती है। यानी सभी कर्मचारियों की कुल सेलरी का 24 प्रतिशत अंशदान मार्केट में निवेश किया जाता है। इसे एलआईसी, यूटीआई या एसबीआई में लगाया जाता है। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो आज तकरीबन 12000 करोड़ रुपए हर महीने एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को मिलते हैं। इससे उनका बिजनेस चलता है। अगर एनपीएस को खत्म कर दिया जाए तो कल से यह पैसा इन तीनों बैंकों को मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन तीनों सरकारी कंपनियों को सरकार, निजीकरण के रास्ते पर धकेल सकती है। अभी दो साल पहले ही भारत सरकार ने एलआईसी की एक तिहायी हिस्सेदारी निजीकरण के तहत बेची थी। इसी तरह कोविड 19 के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी तकरीबन 60000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्र में बेची गई थी। केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक बैंकों का आपस में विलय किया है। वजह, सरकारी क्षेत्र के कई बैंक, घाटे में चल रहे थे।

आज तकरीबन एनपीएस के तहत 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आने वाले चार–पांच साल में यह निवेश, 50 लाख करोड़ को पार कर सकता है। एनपीएस में निवेश की गई रकम, यूनिट की वैल्यू के रूप में है। आज एलआईसी, यूटीआई या फिर एसबीआई की एक यूनिट की वैल्यू लगभग 42 से 44 रुपए के बीच में है। तीन–चार साल पहले यह वैल्यू 20 से 25 रुपये के बीच में थी। अब अगर एनपीएस को रद्द किया जाता है तो जाहिर सी बात है 15 लाख करोड रुपए की वैल्यू घटकर 10 लाख करोड़ से भी नीचे आ सकती है।

इसका मतलब यह हुआ कि 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा कौन पूरा करेगा। वह पैसा कहां से आएगा। आर्थिक नजर से यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके कारण कोई भी राष्ट्रीय दल, ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को मेनिफेस्टो में रखना नहीं चाहता। हालांकि उन्हें कर्मचारियों के वोट लेने हैं, तो वे उनकी भीड़ या आंदोलन में जाकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि वे हूबहू ओपीएस बहाल नहीं कर सकते। हां, अगर उनकी सरकारी बनी तो कर्मचारियों के हित में कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में वे अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को कभी दांव पर नहीं लगा सकते। डॉ. पटेल के अनुसार, अगले 10 सालों में एनपीएस का कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत के स्टॉक मार्केट को किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा आसानी से गिराया नहीं जा सकेगा। संभव है इस लिहाज से एनपीएस को खत्म कर हुबहू ओपीएस बहाल करना एक शगूफा मात्र हो।

अब मुख्य मुद्दा ये है कि ओपीएस कैसे बहाल हो। यह ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आज तक एनपीएस में रिटर्न 9.5 से ज्यादा रहा है, इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के अंशदान पर 7.1 का गारंटिड ब्याज दिया जा सकता है। बचे हुए ब्याज को सरकार अपने फंड में ले सकती है। इससे एनपीएस में ही जीपीएफ की डिमांड पूरी हो सकती है। इस पैसे पर जीपीएफ की तरह विड्रॉल की सुविधा भी दी जा सकती है। हर तीन महीने में सरकार को 91 लाख कर्मचारियों के अंशदान पर लगभग 3 से 4 बचत हो सकती है। दूसरा सरकार अपने अंशदान को सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित वापस ले सकती है। इसके बदले में वह 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले को 50 और इससे कम नौकरी वाले को उसी अनुपात में पेंशन दे सकती है। ये तरीका, हुबहू ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह कारगर साबित हो सकता है। पेंशन पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई भत्ते और पे कमीशन का भी लाभ दिया जा सकता है। पटेल ने कहा, पेंशन बहाली आंदोलन का यही एक सुगम रास्ता समाधान के रूप में निकल सकता है।

गोरखपुर। महिला के भाई ने डॉयल 112 और 108 पर फोन किया। कुछ ही देर में दोनों पहुंच गए। इसके बाद महिला के पति की हालत गंभीर देखते हुए पहले उसे अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। एंबुलेंस में पीछे पति जीवन के लिए जूझ रहा था और आगे की सीट पर उसकी पत्नी से निजी एंबुलेंस चालक और उसका साथी चलती गाड़ी में शर्मनाक हरकतें करते रहे। बस्ती में गाड़ी से उतार कर एंबुलेंस चालक और उसके साथी ने महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश की। सफल नहीं हुए तो पति का ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंक दिया और उसे गाड़ी से उतार कर व महिला के पहने गहने और उसके पास रखी नगदी लेकर फरार हो गए। डॉयल 112 की मदद से महिला के पति को बस्ती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से गोरखपुर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में रविवार को महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी है।

बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 28 अगस्त को अपने बीमार पति को लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाने के कारण अगले दिन महिला ने डॉक्टर से अपनी परेशानी बताते हुए पति को डिस्चार्ज कर देने को कहा। इस पर अस्पताल वाले ने एक प्राइवेट एंबुलेंस का नंबर दिया। उसने उस नंबर पर बात की और बृहस्पतिवार शाम करीब 6.30 बजे एंबुलेंस से पति और 17 साल के भाई के साथ घर के लिए चल दी।

लगभग बीस किलोमीटर चलने के बाद एंबुलेंस चालक ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और महिला से कहा कि रात का मामला है, रास्ते में पुलिस गाड़ी चेक करती है। तुम आगे बैठ जाओ, तो पुलिस गाड़ी नहीं रुकवाएगी। महिला के अनुसार, पहले तो उसने मना कर दिया लेकिन उसके कई बार कहने पर मजबूरी में आगे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने उसके भाई को पीछे की सीट पर बैठा दिया। आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर व उसके साथी ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी।

महिला के बार–बार मना करने के बावजूद भी वह नहीं मान रहे थे। इस पर वह शोर मचाने लगी, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद होने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। हालांकि उसकी चीख सुनकर पीछे की सीट पर बैठे भाई को कुछ गलत होने का अहसास हुआ तो उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। करीब डेढ़ सौ किमी तक एंबुलेंस चालक और उसके साथी महिला से शर्मनाक करते रहे। रात करीब 11.30 बजे बस्ती जिले के छावनी क्षेत्र में एंबुलेंस चालक ने गाड़ी रोक दी।

षाहजहांपुर । मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पड़ोसियों से पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए सिंधौली के गांव तिउलक निवासी संजीव कुमार ने अपने पांच साल के पुत्र गौरव को नदी में फेंककर मार डाला। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर पड़ोसियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। शक होने पर पुलिस ने भरोसे में लेकर संजीव से पूछताछ की। इससे पूरा मामला खुल गया। मंगलवार को खन्नौत नदी से बच्चे का शव बरामद कर लिया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सोमवार को शाम करीब छह बजे संजीव ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ पांच साल के पुत्र गौरव का गांव के बाबूराम, विवेक, विशाल, रिंकू ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने विवेचना शुरू की। संजीव बार–बार अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगा रहा था। शक होने पर पुलिस ने उसे भरोसे में लिया और पूछताछ शुरू की। उसे आश्वस्त किया कि शव मिलने पर हत्या की धारा लग जाएगी। इतनी बात सुनकर उसने नदी में तलाश करने को कहा। सिंधौली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सुबह चार बजे शव को बरामद कर लिया। इसके बाद संजीव से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संजीव की करतूत सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान रह गए।

एसपी देहात मनोज अवस्थी ने बताया कि कुछ माह पहले पड़ोसी विवेक व संजीव पक्ष में झगड़ा हो गया था। संजीव की पत्नी नन्हीं देवी शिकायत करने गई तो वहां उसके साथ मारपीट कर दी गई थी। इसी बेइज्जती का बदला लेने को संजीव ने दवा दिलाकर लौटते समय बेटे को पुल से नदी में धक्का दे दिया और थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

बदले की आग में हैवान बना पिता: बेटे को नदी में फेंककर मार डाला, पुलिस से बोला– पड़ोसियों ने की हत्या

संवाद न्यूज, शाहजहांपुर। साहब...पड़ोसियों ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। इनके ऊपर हत्या की धारा लगाकर जेल भेज देना। अपने मासूम बेटे की हत्या करने के आरोपी संजीव के बार–बार यही बात दोहराने पर पुलिस का शक उस पर गहराता गया। पड़ोसियों को थाने में बुलाने के बाद पुलिस ने संजीव को कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब पुलिस ने ये कहा कि शव बरामद होते ही पड़ोसियों को जेल भेज देंगे। वैसे ही संजीव ने नदी में खोजने की बात कही। पुलिस ने मंगलवार को मासूम का शव नदी से बरामद कर लिया। हत्यारोपी पिता को जेल भेज दिया।

सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव तिउलक निवासी राजमिस्त्री संजीव ने पत्नी नन्हीं देवी की पिटाई का बदला लेने के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की हत्या कर दी। पत्नी से विवाद के बाद से ही पड़ोसियों को उसने सबक सिखाने की ठान ली थी। संजीव घर लौटा। उसने पत्नी को बताया कि उसे बुखार आ रहा है। इसके बाद साजिश के तहत बेटे गौरव व खुद की दवा लेने के लिए स्कूटी से चिनौर आया था। खुशीराम के मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बाद शाम करीब सात बजे वह तिउलक पुल के पास पहुंचा। लोगों की आवाजाही न होने के दौरान उसने मासूम बेटे गौरव को पुल से नदी में धक्का दे दिया। आंखों के सामने वह डूब गया और उसका निर्दयी पिता उसे देखता रहा। बेटे के पानी में डूबने के बाद संजीव घर पहुंचा। उसने बताया कि पड़ोसी और चार अन्य लोग रास्ते में घेरकर बेटे को छीनकर भाग गए। इतना कहते हुए वह बेहोश हो गया। उसे पानी की छींटें मारकर होश में लाया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने संजीव से पूछताछ शुरू की।

स्लीवलेस ड्रेस में सना मकबूल लगीं बेहद खूबसूरत

बिना हीरो पर्दे पर धमाल मचा चुकी हैं ये अभिनेत्रियां
अपनी अदाकारी के दम पर दी कई फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क। सिनेमा जगत में किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए अभिनेता और अभिनेत्री दोनों की ही जरूरत होती है। कुछ फिल्मों में अभिनेत्रियों को केवल अभिनेता की सहायक हीरोइन के रूप में ही रखा जाता है, बाकी पूरी फिल्म में केवल अभिनेता की ही अहम भूमिका होती है। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में पुरुष प्रधान होती हैं। अभिनेताओं के मुकाबले अभिनेत्रियों के काम की तारीफ कम होती है। वहीं, बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं, जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा है। उन्होंने फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर यह साबित किया है कि बिना अभिनेताओं के भी फिल्में हिट हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपने अदाकारी के दम पर फिल्में हिट करवाई हैं।

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा का है। रेखा ने ही सबसे पहले इस ट्रेंड की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने दम पर कई फिल्में सुपरहिट करवाई हैं। दर्शक उनकी दमदार अदाकारी के दीवाने हैं। 1990 में फिल्म 'घटा' से रेखा ने यह ट्रेंड शुरू किया था। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था। इसके बाद तो रेखा ने कई महिला प्रधान फिल्मी कीं। इसमें 'खून भरी मांग', 'फुल बने अंगारे', 'बीवी हो तो ऐसी', 'उमराव जान', 'सुपर नानी', 'बहुरानी', 'यह आग कब बुझेगी' फिल्में शामिल हैं। अपनी शानदार अदाकारी के दम पर रेखा ने यह फिल्में सुपरहिट करवाई हैं।

इस लिस्ट में अगला नाम कंगना रनौत का है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने कई महिला प्रधान फिल्में की हैं और वे सभी फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई हैं। अभिनेत्री कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वही रूप उनका फिल्मों में भी दिखाई देता है। आज के दौर में भी कंगना ने यह साबित किया है कि बिना हीरो की अहम भूमिका के भी फिल्म पर्दे पर कमाल दिखा सकती है। कंगना ने 'क्वीन', 'रिवॉल्वर रानी' और 'मणिकर्णिका' जैसी सुपर हिट फिल्में दी हैं। वहीं, अब वे 'इमरजेंसी' को लेकर भी चर्चा में हैं।

बॉलीवुड की खंडाला गर्ल कही जाने वाली रानी मुखर्जी भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुई हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भी अपने करियर में कई फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में काम किया है। रानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ही महिला प्रधान फिल्म से की थी। उन्होंने फिल्म 'राजा की आएगी बारात' में अपनी अदाकारी से जान डाल दी थी। हालांकि यह फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद रानी मुखर्जी ने फिल्म 'हिचकी' और 'मर्दानी' में अपनी अदाकारी का जौहर बिखेरा और ये फिल्में सुपरहिट साबित हुईं।

फाल्गुनी शेन पीकाक के स्टोर लान्च में पहुंची गौरी खान, कहा– हर स्टोर नई प्रेरणा लेकर आता है

कॉलेज में थिएटर से की थी सरगुन मेहता ने अभिनय की शुरुआत

एंटरटेनमेंट डेस्क। फैशन ब्रांड फाल्गुनी शेन पीकॉक ने गुरुवार को नई दिल्ली के द धन मिल में अपने प्रीवियर स्टोर का अनावरण किया। यह उद्घाटन और भी खास था, क्योंकि इस दिन ब्रांड की 20वीं वर्षगांठ थी और यह उसका प्रतीक बना। बता दें कि इस स्टोर को गौरी खान डिजाइन किया है।

गौरी खान ने पिछले कुछ सालों में कई हाई–एंड प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में उनका डिजाइन सेंस विकसित हुआ है। गौरी ने कहा, 'हर प्रोजेक्ट के साथ मेरा डिजाइन सेंस हर दिन विकसित होता है, जो नई प्रेरणा और एक नया नजरिया लेकर आता है।' जब उनसे पूछा गया कि स्टोर बनाने के पीछे क्या था, तो गौरी ने कहा, 'फाल्गुनी और शेन के स्टोर को डिजाइन करना उनकी शैली को एक भौतिक स्थान में बदलने के बारे में था। हमारा उद्देश्य उनके लक्जरी प्रीटवियर लाइन को फिर से नए इंटीरियर के साथ दिखान था।'

ब्रांड के दो दशक के पूरे होने पर स्टोर को और भी खास बनाने के लिए, गौरी ने एक 'पर्सनल टच' जोड़ा। उन्होंने कहा, 'फाल्गुनी और शेन की दो दशकों के सफर का जश्न मनाने के लिए, हमने कस्टम पीतल मोनोग्राम फर्नीचर जैसी चीजों जोड़ा।' अपने सफर को "अविश्वसनीय" बताते हुए गौरी ने कहा, 'अविश्वसनीय, प्रत्येक परियोजना सीखने और रचनात्मकता से भरा एक नया रोमांच रहा है। मेरी शैली मेरे द्वारा डिजाइन किए गए प्रत्येक स्थान के साथ विकसित होती है और बढ़ती है।' नए स्टोर को खरीदारों को फाल्गुनी शेन पीकॉक के तैयार किए कलेक्शन के लिए इस जगह को डिजाइन किया गया है।' बता दें कि गौरी ने अपने पति, शाहरुख खान के नए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) कार्यालय को भी तैयार किया है। इसके अलावा, गौरी ने उपनगरीय मुंबई में कई रेस्तरां और सेलिब्रिटी घरों का नवीनीकरण किया है।

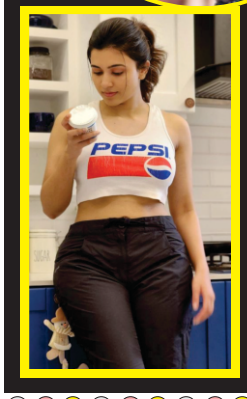

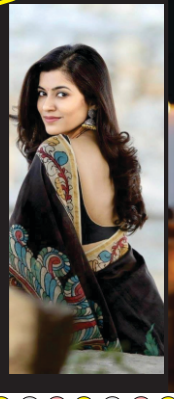

प्रोटेस्ट में एक्ट्रेस के खिलाफ लगे नारे
रितुपर्णा ने लगाया धक्का देने का आरोप–

'मैं मर सकती थी'

मुंबई। चंकी पांडे, मिथुन चकवर्ती, रितेश देशमुख और सनी देओल समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स संग काम कर चुकी एक्ट्रेस बंगाली एक्ट्रेस रितुपर्णा सेनगुप्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची. एक्ट्रेस वहां हो रहे प्रोटेस्ट के सपोर्ट में पहुंची थीं. लेकिन उन्हें प्रोटेस्टर्स के विरोध का सामना करना पड़ा. रैली में रितुपर्णा 'गो बैक' के नारे लगे. इस विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन एक्ट्रेस ने बाद में बताया कि उनके साथ इतनी तेज धक्का–मुक्की हुई कि वह मर सकती थीं. इतना ही उनकी कार को भी पीटा.रितुपर्णा सेनगुप्ता ने आजतक बांग्ला को दिए इंटरव्यू में कहा,"जिस तरह से वे मुझे धक्का दे रहे थे, मैं मर सकती थी. उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. यंग लड़के और लड़कियों ने मेरी कार को पीटना शुरू कर दिया. कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे. उनका नाम नहीं बताया गया है. वे संभवतः विरोध प्रदर्शनों में इसी तरह से शामिल होते हैं. ऐसे तत्व विरोध को गलत दिशा दे रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं."

केबीसी शो पर अमन और अमित सर के साथ हंसी–मजाक और ज्ञान का अनोखा मेला!

नवारो, सबालेंका और फ्रिट्ज सेमीफाइनल में

बोपन्ना–सुत्जियादी की जोड़ी अंतिम–4 के मैच में हारी

स्पोर्ट्स डेस्क। दूसरी वरीयता प्राप्त सबालेंका को पिछले महीने पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग क्विनवेन को 6–1, 6–2 से पराजित करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। अमेरिका की एम्मा नवारो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना आर्यना सबालेंका से होगा। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंचने वाली 13वीं वरीयता प्राप्त नवारो ने मंगलवार को फ्लशिंग मीडोज में हमवतन पाउला बडोसा को 6–2, 7–5 से हराया।

नवारो क्वार्टर फाइनल के इस मैच के दूसरे सेट में एक समय पीछे चल रही थी लेकिन उन्होंने आखिरी छह गेम जीत कर पासा पलट दिया। उन्होंने पिछले मैच में गत चैंपियन कोको गॉफ के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन किया था। दूसरी वरीयता प्राप्त सबालेंका को पिछले महीने पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग क्विनवेन को 6–1, 6–2 से पराजित करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर भी इस मैच के गवाह बने। संन्यास लेने के बाद पहली बार वह दर्शक के रूप में अमेरिकी ओपन में पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन सबालेंका साल का दूसरा और कुल मिलाकर तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने की कवायद में हैं। वह अमेरिकी ओपन में लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं। सबालेंका पिछले साल उपविजेता रही थी।

बेलारूस की 26 वर्षीय सबालेंका ने मैच के बाद कहा, 'जब मैंने दर्शकों के बीच फेडरर को देखा तो मुझे लगा कि वह फ्रांसिस टियाफो और ग्रिगोर दिमित्रोव का मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेलना है ताकि वह इसका आनंद उठा सकें।' पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में अमेरिका के 12वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने अमेरिकी ओपन में 2020 के उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 7–6 (2), 3–6, 6–4, 7–6 (3) से हराकर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह बनाई।

बोपन्ना और सुत्जियादी की जोड़ी सेमीफाइनल में हारी

भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनकी इंडोनेशियाई जोड़ीदार अल्डिला सुत्जियादी मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड की अमेरिकी जोड़ी से 3–6, 4–6 से हारकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारत और

इंडोनेशिया की जोड़ी ने इससे पहले एक घंटे 30 मिनट से अधिक समय तक चले क्वार्टर फाइनल मैच में मैथ्यू एबडेन और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा को हराया था। 44 वर्षीय बोपन्ना पहले ही पुरुष युगल से बाहर हो गए थे। उनकी और एबडेन की जोड़ी तीसरे दौर में मैक्सिमो गोंजालेज और आंद्रेस मोल्टेनी की अर्जेंटीना की 16वीं वरीय जोड़ी से 1–6, 5–7 से हार गई थी। इससे पहले टूर्नामेंट में, सुमित नागल पुरुष एकल के पहले दौर में हार गए थे, जबकि युकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भी पुरुष युगल के अलग–अलग चरणों में हारकर बाहर हो गए थे।

ऊंची कूद में शरद, भाला फेंक में अजीत की चांदी

भारत ने 20 पदक जीत टोक्यो को पीछे छोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पेरिस पैरालंपिक में टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने दो रजत और चार कांस्य के साथ छह पदक और जीतते हुए पदकों की संख्या 20 पहुंचा दी। टोक्यो में भारत ने 19 पदक जीते थे। मंगलवार को ऊंची कूद में शरद कुमार ने 1.88 मीटर ऊंचाई पार कर रजत और टी मरियप्पन ने 1.85 मीटर के साथ कांस्य जीता। वहीं, भाला फेंक में अजीत सिंह ने 65.62 मीटर के साथ रजत और सुंदर सिंह गुर्जर 64.96 मीटर के साथ कांस्य जीता।

साथ ही तेलंगाना की दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर दौड़ में 55.82 सेकंड के साथ कांस्य जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भारतीय एथलीट्स ने कमाल करते हुए छह पदक जीते। इनमें दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। जेवलिन थ्रो की थ46 श्रेणी में अजीत सिंह तो हाई जंपर शरद कुमार ने ऊंची कूद की टी63 श्रेणी में मंगलवार को रजत पदक जीता। इसी के साथ इस पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या अब तक 20 पहुंच चुकी है। पदकों की यह संख्या अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। अपने ट्रैक एवं फील्ड एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के19 पदकों के अपने पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि भारत इस बार 25 पार के लक्ष्य को लेकर इन खेलों में उतरा है। ऐसे में भारतीय एथलीट्स इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अवनि लेखरा से शुरू हुई कहानी जारी है। पेरिस पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीट्स भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन खेलों का आयोजन आठ सितंबर तक होना है। भारत 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो टोक्यो से तीन ज्यादा हैं।

ऊंची कूद टी63 वर्ग स्पर्धा में भारत ने जीता रजत और कांस्य

पेरिस में हो रहे पैरालंपिक 2024 खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद टी 63 वर्ग स्पर्धा में मंगलवार को भारतीय पैरा एथलीट्स ने रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। देर रात हुए फाइनल मुकाबले में हाई जंपर शरद कुमार ने 1.88 मीटर की दूरी तय कर सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए 1.85 मीटर की दूरी तय की। उन्हें कांस्य पद दिया गया। बता दें कि टोक्यो पैरालिंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं, विश्व रिकॉर्ड धारक यूएसए के फ्रेच एज्रा ने स्वर्ण पदक जीता।

पुरुष भाला फेंक एफ 46 वर्ग स्पर्धा में में भी आए पदक

भारत के स्टार भाला फेंक पैरा एथलीट अजीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस पैरालंपिक में पुरुष भाला फेंक एफ 46 वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। अजीत सिंह ने भाला फेंक थ46 फाइनल में अजीत सिंह ने 65.62 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। वहीं, इसी स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने भी सीजन के अपने सर्वश्रेष्ठ 64.96 थ्रो के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

साथ ही तेलंगाना की दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर दौड़ में 55.82 सेकंड के साथ कांस्य जीता।

पांच साल की उम्र में हादसे में मरियप्पन ने गंवाया था अपना पैर

मरियप्पन का जन्म तमिलनाडु के पेरियावदमगट्टी गांव में हुआ, जो सेलम से करीब 50 किलोमीटर दूर है। पांच साल की उम्र में मरियप्पन एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके चलते उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। बहन को बचाते समय एक ट्रक उनके पैर के ऊपर से गुजर गया। मरियप्पन के पिता कई साल पहले परिवार को छोड़ कर चले गए थे। इसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आए और मरियप्पन के परिवार के लिए दिक्कतें और बढ़ गईं। उनकी मां साइकिल से सब्जी बेचती थीं। मरियप्पन को शुरुआत में वॉलीबॉल में दिलचस्पी थी। अपनी हालत के बावजूद वो स्कूल में वॉलीबॉल खेलते थे। मगर बाद में उनकी टीचर ने उन्हें हाई–जंप के लिए प्रेरित किया। मरियप्पन ने 14 साल की उम्र में सामान्य खिलाड़ियों को हराकर सिल्वर मेडल जीता। 2015 में मरियप्पन वर्ल्ड नंबर वन बने।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	चीन	53	40	22	115
2	ब्रिटेन	30	18	13	61
3	अमेरिका	20	22	11	53
4	ब्राजील	14	11	23	48
5	फ्रांस	11	12	15	38
6	इटली	10	8	17	35